

**भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.4223  
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025**

**कर्नाटक में भारतनेट परियोजना**

**4223. श्री पी.सी. मोहन :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट चरण-1 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने कर्नाटक के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड की तैनाती में किसी चुनौती की पहचान की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) 2025-26 के बजट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत कर्नाटक में भारतनेट के लिए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (ग) कर्नाटक सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट चरण-1 के तहत कर्नाटक की 6084 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। राज्य की शेष 6 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना और नेटवर्क को और मजबूत करना संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यक्षेत्र में है। एबीपी में राज्य के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों सहित मांग के आधार पर सभी गैर-ग्राम पंचायत गांवों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना भी शामिल है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतनेट परियोजना के लिए कर्नाटक सहित पूरे देश के लिए केंद्रीय बजट (2025-26) में 22,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*\*